कच्छी लाल रामेश्वर आश्रम ट्रस्ट एवं

अन्ना क्षेत्र ट्रस्ट श्री वेलजी देवर्षि पटेल

बनाम

कलेक्टर, हरिद्वार एवं अन्य।

(सिविल अपील क्रमांक 3878/2009)

सितम्बर 22, 2017

[एन.वी. रमना और डॉ. डी.वाई. चंद्रचूड़, जे.जे.]

क्षेत्राधिकार:

कलेक्टर का क्षेत्राधिकार- यह निर्णय देने में कि प्रश्न में निर्वसीयत संपत्ति राज्य सरकार में निहित होगी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 29 के अर्थ के तहत उत्तराधिकारियों की विफलता का परिणाम है- माना गया: धारा 29 के तहत मुद्दों को निर्धारित करने की प्रक्रिया में, कलेक्टर ने विभिन्न विवादित तथ्यात्मक मामलों पर फैसला सुनाया- एक सिविल न्यायालय के पास नागरिक विवादों से जुड़े सभी मामलों पर फैसला करने का अधिकार क्षेत्र है, सिवाय इसके कि जहां अदालत का क्षेत्राधिकार छीन लिया गया है- ऐसे मामले पर कलेक्टर द्वारा अधिकार क्षेत्र मानकर फैसला नहीं किया जा सकता था जो उसे कानून द्वारा प्रदान नहीं किया गया है- प्रशासनिक प्राधिकारियों को नागरिक विवादों से जुड़े स्वामित्व के मामलों पर निर्णय लेने की अनुमति देना कानून के शासन के लिए विनाशकारी होगा- शीर्षकों का निर्णय सीपीसी की धारा 9- सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908- धारा 9- हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956- धारा 29 भारत के संविधान के तहत सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के सामान्य नागरिक क्षेत्राधिकार का सहारा लेना चाहिए: अनुच्छेद 142- के अंतर्गत

क्षेत्राधिकार- धारण का दायरा: सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त संवैधानिक क्षेत्राधिकार का आधार न्याय की उन्नति है- न्याय प्रदान करने की न्यायालय की शक्ति को उसके अधिदेश के प्रति एक संकीर्ण दृष्टिकोण द्वारा सीमित नहीं किया जाना चाहिए -

अनुच्छेद 142 के पीछे का सिद्धांत पूर्ण न्याय प्रदान करना है- जब अदालत शुरू में सीमित नोटिस जारी करती है और बाद में छुट्टी दे देती है, तो अपील का दायरा अधिकार क्षेत्र का नहीं, बल्कि न्यायिक विवेक का मामला उठाता है : इसलिए मार्गदर्शक सिद्धांत पर्याप्त न्याय की उन्नति होगी- अपील की अंतिम सुनवाई के समय, सुप्रीम कोर्ट नोटिस जारी करने के समय दिए गए किसी भी आदेश से बाधित नहीं होगा और विवाद अपने पूरे परिप्रेक्ष्य में विचार के लिए खुला रहेगा- अभ्यास और प्रक्रिया।

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956:

धारा 29- का दायरा- माना गया: धारा 29 एक सिद्धांत का प्रतीक है, लेकिन विवादित प्रश्नों पर निर्णय के लिए एक प्रक्रियात्मक तंत्र प्रदान नहीं करता है- धारा 29 राजद्रोह के सिद्धांत का प्रतीक है और केवल उत्तराधिकारियों के होने पर ही लागू होता है।

सिद्धांत/सिद्धांत: पलायन का सिद्धांत- चर्चा की गई।

प्रमाण: उत्तरदायित्व- राजद्रोह के मामले में- माना जाता है: जब राजद्रोह का प्रश्न उठता है, तो मामले को स्थापित करने का दायित्व बहुत हद तक उस व्यक्ति पर होता है जो यह दावा करता है कि जिस व्यक्ति की वसीयत किए बिना मृत्यु हो गई है, उसकी संपत्ति पर उत्तराधिकार पाने के लिए योग्य उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति है।

प्रशासक- सामान्य अधिनियम, 1963:

प्रशासक जनरल की शक्तियां- का दायरा- धारित: प्रशासक जनरल को किसी मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के प्रशासन को सुरक्षित रखने के लिए कर्तव्यों और दायित्वों से सम्मानित किया जाता है- कानून ने उसके लिए कोई न्यायिक शक्ति आरक्षित नहीं की है- ऐसे न्यायिक कार्य उच्च न्यायालय को सौंपे जाते हैं।

एक शिकायत के अनुसार, कलेक्टर (प्रतिवादी संख्या 1) ने माना कि अपीलकर्ता के कब्जे में संपत्ति-ट्रस्ट हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 29 के तहत राज्य सरकार में निहित है क्योंकि संपत्ति के मालिक ('एम') की मृत्यु के बाद संपत्ति का उत्तराधिकारी कोई उत्तराधिकारी नहीं था। कलेक्टर के आदेश को ट्रस्ट ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर चुनौती दी थी। कलेक्टर के आदेश को बरकरार रखते हुए रिट याचिका खारिज कर दी गई।

उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका में, इस न्यायालय ने इस प्रश्न तक सीमित नोटिस जारी किया कि क्या कलेक्टर के पास प्रशासक- सामान्य अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के मद्देनजर धारा 29 के तहत आदेश जारी करने की शक्ति थी। इसके बाद अनुमति दे दी गई।

प्रतिवादी-राज्य ने अन्य बातों के साथ-साथ तर्क दिया कि चूंकि नोटिस एक सीमित प्रश्न तक ही सीमित था, इसलिए बाद में छुट्टी देना भी उसी मुद्दे तक सीमित होना चाहिए और विवाद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अपील में उठाए गए सभी मुद्दों तक विस्तार किया जाए।

अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय ने कहा:

1. सर्वोच्च न्यायालय को जो संवैधानिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है, उसका आधार न्याय की उन्नति है। न्याय प्रदान करने की न्यायालय की शक्ति को उसके अधिदेश के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण द्वारा सीमित नहीं किया जाना चाहिए। संविधान का

अनुच्छेद 142 इस मूल सिद्धांत का प्रतीक है कि अदालत का अधिकार क्षेत्र पूर्ण न्याय प्रदान करना है और इसकी एक घटना के रूप में, अदालत ऐसे डिक्री या आदेश पारित कर सकती है जो वह उचित समझे। जब न्यायालय शुरू में एक सीमित नोटिस जारी करता है लेकिन बाद में छुट्टी दे देता है, तो पेशी का दायरा क्षेत्राधिकार का नहीं बल्कि न्यायिक विवेक का मामला उठाता है। चूंकि यह विवेक का मामला है न कि अधिकार क्षेत्र का, इसलिए मार्गदर्शक सिद्धांत पर्याप्त न्याय की उन्नति होना चाहिए। अंतिम सुनवाई के समय, इसे "इसके संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में" विवाद पर विचार करने से रोका नहीं जाएगा और ऐसा करते समय, यह "नोटिस जारी करने के समय किए गए किसी भी अवलोकन, किसी भी आदेश से बाधित नहीं होगा"। [पैरा 16 और 171 1778-ए-बी; 779-ए-डी]

योमेशभाई प्राणशंकर भट्ट बनाम गुजरात राज्य (2011) 6 एससीसी 312: 120111 6 एससीआर 958; उत्तरांचल राज्य बनाम आलोक शर्मा (2009) 7 एससीसी 647: [2009] 7 एससीआर 1; इंडियन बैंक बनाम गोधरा नागरिक सहकारी क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड (2008) 12 एससीसी 541: (2008} 9 एससीआर 450- पर भरोसा किया गया।

2.1 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 29 राजद्रोह के सिद्धांत का प्रतीक है। राजद्रोह का सिद्धांत यह मानता है कि जहां कोई व्यक्ति बिना वसीयत किए मर जाता है और अपने पीछे कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ता जो संपत्ति का उत्तराधिकारी होने के योग्य हो, तो संपत्ति सरकार को हस्तांतरित हो जाती है। हालाँकि ऐसी स्थिति में संपत्ति सरकार को हस्तांतरित हो जाती है, फिर भी सरकार इसे अपने सभी दायित्वों और देनदारियों के अधीन लेती है। दूसरे शब्दों में, राज्य संपत्ति को "मृतक के प्रतिद्वंद्वी या अधिमान्य उत्तराधिकारी के रूप में नहीं, बल्कि देश की संपूर्ण धरती के स्वामी सर्वोपरि" के रूप में लेता है। धारा 29 केवल उत्तराधिकारियों के असफल होने पर ही

लागू होती है। विफलता का अर्थ है बिना वसीयत के मरने वाले व्यक्ति के किसी भी उत्तराधिकारी की पूर्ण अनुपस्थिति। [पैरा 18] (779-एफ-एच; 780-ए-बीजे

पंजाब राज्य बनाम बलवंत सिंह (1992) सप्ल (3) एससीसी 108 .... पर भरोसा किया।

इंग्लैंड के हेल्सबरी के कानून, चौथा संस्करण, खंड 17, पैरा 1439- संदर्भित।

2.2 जब राजद्रोह का प्रश्न उठता है, तो जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर बहुत अधिक होती है जो उस व्यक्ति की संपत्ति पर उत्तराधिकार के लिए योग्य उत्तराधिकारी के स्नेह का दावा करता है जो पीछा स्थापित करने के लिए बिना वसीयत के मर गया है। कानून ऐसे परिणाम को आसानी से स्वीकार नहीं करता। [पैरा 18] [780-बी-सी]

बिहार राज्य बनाम राधा कृष्ण सिंह (1983), 3 एससीसी 118: [1983] 2 एससीआर 808- पर निर्भर।

मुल्ला का हिंदू कानून बाईसवां संस्करण, पृष्ठ 1260-1561-उद्धृत।

2.3 यहां तक कि ऐसी स्थिति में भी जहां कोई संस्थापक या उसकी वंशावली विलुप्त हो गई है, और संपत्तियां राज्य के पास चली जाती हैं, राज्य जो एक समर्पित संपत्ति प्राप्त करता है वह ट्रस्ट के अधीन है और इसे धर्मनिरपेक्ष संपत्ति के रूप में व्यवहार नहीं कर सकता है। वास्तव में, धारा 29 स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि राज्य "संपत्ति को उन सभी दायित्वों और देनदारियों के अधीन ले लेगा जिनके अधीन एक उत्तराधिकारी होता।" [पैरा 18} [781-जी-एच; 782-ए]

2.4 वर्तमान मामले पर निर्णय लेते समय, इस न्यायालय को स्थापित सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक किसी गणित या धार्मिक संस्थान के संस्थापक ने बंदोबस्ती के उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत को निर्धारित

नहीं किया है, उत्तराधिकार को संस्थान के रीति-रिवाज या उपयोग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। [पैरा 19] {1782-बी]

रामबीर दास बनाम कल्याण दास (1997) 4 एससीसी 102: [1997] 2 एससीआर 210; महंत सीतल दास बनाम संत राम एआईआर 1954 एससी 606-पर भरोसा किया गया।

2.5 कलेक्टर का आदेश इंगित करता है कि यह मुद्दा कि धारा 29 के अर्थ के तहत हेरिस की विफलता के परिणामस्वरूप संपत्ति राज्य सरकार में निहित होगी या नहीं, परस्पर विरोधी दावों के निर्णय पर एक गंभीर रूप से विवादित मुद्दा था। कथित तौर पर धारा 29 के तहत मुद्दे को निर्धारित करने की प्रक्रिया में, कलेक्टर ने विभिन्न तथ्यात्मक मामलों पर निर्णय लिया है। धारा 29, एक सिद्धांत का प्रतीक है लेकिन विवादित प्रश्नों पर निर्णय के लिए कोई प्रक्रियात्मक तंत्र प्रदान नहीं करती है। न्यायालय के समक्ष विवाद का कैनवास उन मामलों का प्रचुर संकेत है जो गंभीर रूप से विवाद में थे। राज्य का यह तर्क कि मालिक को मृत मान लिया गया है और अपने पीछे कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं छोड़े जाने के परिणामस्वरूप संपत्ति उसे हस्तांतरित हो जाएगी, गंभीर रूप से सवालों के घेरे में है। इस तरह के मामले पर कलेक्टर द्वारा खुद को एक क्षेत्राधिकार मानते हुए निर्णय नहीं लिया जा सकता था जो कानून द्वारा उसे प्रदान नहीं किया गया है; [पैरा 201 [782-एफ, जी; 782-बी, सी]

2.6 सिद्धांत यह है कि कानून आसानी से धोखाधड़ी के दावे को स्वीकार नहीं करता है और जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर बहुत अधिक निर्भर करती है जो दावा करता है कि एक व्यक्ति बिना वसीयत के मर गया है, और उसके पास कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, जो संपत्ति के लिए योग्य हो, एक ठोस तर्क पर आधारित है। एस्केट एक सिद्धांत है जो राज्य को सर्वोपरि संप्रभु के रूप में मान्यता देता है, जिसकी संपत्ति केवल उत्तराधिकारियों की विफलता के स्पष्ट और स्थापित मामले पर ही निहित होगी। यह

सिद्धांत इस मानदंड पर आधारित है कि कानून के शासन द्वारा शासित समाज में, न्यायालय यह नहीं मानेगा कि निजी स्वामित्व को अधिरोहित किया गया है। शासी वैधानिक प्रावधान के आधार पर कोई स्पष्ट मामला न होने पर, राज्य के पक्ष में। राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों- जिसमें वर्तमान मामले में कलेक्टर भी शामिल है- को नागरिक विवादों से जुड़े स्वामित्व के मामलों पर निर्णय लेने की अनुमति देना कानून के शासन के लिए विनाशकारी होगा। कलेक्टर राज्य का एक अधिकारी होता है। वह केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो कानून उसे निजी विवादों में प्रवेश करने के लिए विशेष रूप से प्रदान करता है। इसके विपरीत, एक सिविल न्यायालय के पास नागरिक विवादों से जुड़े सभी मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र है, सिवाय इसके कि जहां न्यायालय जेएस का अधिकार क्षेत्र, या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा, क़ानून द्वारा छीन लिया गया है। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के तहत स्वामित्व पर निर्णय के लिए सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के सामान्य नागरिक क्षेत्राधिकार का सहारा लिया जाना चाहिए। [पैरा 21 (783-डी-जी; 784-ए, बी.जे.)

2. कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया और न्यायिक कार्यवाही शुरू कर दी। यह शक्ति उसमें निहित नहीं थी। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 167 की उपधारा 2 द्वारा कलेक्टर को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग केवल उपधारा 1 में निर्धारित परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, प्रावधान स्पष्ट रूप से आकर्षित नहीं हुआ था . [पैरा 24 और 27) [789-सी; 790-ए.जे

3. प्रशासक-सामान्य अधिनियम, 1963 के प्रावधान प्रशासक जनरल में निहित शक्तियों के दायरे और उन परिस्थितियों को परिभाषित करते हैं जिनमें वह उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है। अनिवार्य रूप से, प्रशासक जनरल उस व्यक्ति की

संपत्ति की रक्षा के लिए कदम उठाता है जिसकी मृत्यु हो गई है और ऐसा कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया है जिसके लिए किसी भी अदालत के पास संपत्ति के प्रशासन का अधिकार क्षेत्र हो। जहां मृतक की संपत्ति या संपत्ति आसन्न खतरे में है, उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासक जनरल को संपत्ति की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का अधिकार दिया जा सकता है। प्रशासक जनरल को प्रशासन पत्र प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करने की अनुमति देते हुए, कानून किसी अन्य व्यक्ति को उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और दावा स्थापित करने की अनुमति देता है। जहां प्रशासक जनरल की प्राथमिकता में प्रोबेट या प्रशासन पत्र का दावा स्थापित हो जाता है, वहां उच्च न्यायालय द्वारा निरस्तीकरण का आदेश पारित किया जा सकता है। ऐसे न्यायिक कार्य उच्च न्यायालय को सौंपे जाते हैं। प्रशासक जनरल, एक सार्वजनिक अधिकारी के रूप में, क़ानून में विज्ञापित परिस्थितियों में एक मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के प्रशासन को सुरक्षित और संरक्षित करने के कर्तव्यों और दायित्वों से सम्मानित किया जाता है। कानून ने प्रशासक जनरल को न्यायिक शक्ति आरक्षित नहीं की है। संसद ने अपने विवेक से प्रशासक जनरल को ऐसी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देकर यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए हैं कि जो व्यक्ति अपने पीछे कानूनी उत्तराधिकारी नहीं छोड़ते हैं उनकी मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति बर्बाद न हो। उच्च न्यायालय को न्यायिक कार्य सौंपने से सत्ता के दुरुपयोग से सुरक्षा मिलती है और निजी दावों पर निर्णय की सुविधा मिलती है। [पैरा 23] [788-ई-एच; 789-ए, बी.जे.-

केस कानून संदर्भ

[2011) 6 एससीआर 958	निर्भर	पैरा 16
[2009) 7 एससीआर 1	निर्भर	पैरा 16

[2008) 9 एससीआर 450	निर्भर	पैरा 16
(1992) पूरक (3) धारा 108	निर्भर	पैरा 18
[1983) 2 एससीआर 808	निर्भर	पैरा 18
[19971 2 एससीआर 210	निर्भर	पैरा 18
एआईआर 1954 एससी 606	निर्भर	पैरा 19

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 3878/2009

रिट याचिका संख्या 477 (एम/बी)/2003 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित अंतिम आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 15.05.2007 से।

उपस्थित पक्षों के लिए सी.ए.सुंदरम, सुशील कुमार जैन, भुवनेश्वरी पाठक, एम.एन. राव, वरिष्ठ अधिवक्ता, पुनीत जैन, मनीष मनोचा, सुश्री रोहिणी मूसा, अभिषेक गुप्ता, जफर लेनायत, अपूर्व त्रिपाठी, सुश्री क्रिस्टी जैन (सुश्री प्रतिभा जैन के लिए), अभिनव गुप्ता, प्रियाल जैन, हर्ष जैन, सुश्री शिल्पी सत्य प्रिया सत्यम, राहुल कौशिक सुश्री प्रोर्निला, आशुतोष कुमार शर्मा (जतिंदर कुमार भाटिया के लिए), एस.आर.सेतिया, सलाहकार।

न्यायालय का फैसला न्यायाधीश डी.आर.डी.चंद्रचूड़ द्वारा सुनाया गया।

1. यह अपील 15 मई 2007 को नैनीताल में उत्तराखंड उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले से उत्पन्न हुई है। संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका में कोई तथ्य नहीं पाते हुए, उच्च न्यायालय ने 12 मई 2003 को कलेक्टर, हरिद्वार द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि विवादित संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 29 के तहत सरकार में निहित है। यह खोज

इस आधार पर की गई है कि मोहन लाल की मृत्यु के बाद संपत्ति का उत्तराधिकारी कोई उत्तराधिकारी नहीं है।

2. याचिकाकर्ता का दावा है कि वह बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950 के तहत पंजीकृत एक सार्वजनिक ट्रस्ट है। ट्रस्ट का दावा है कि उसके पास हरिद्वार में बड़ी मात्रा में संपत्ति है जिसका उपयोग धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है- (i) हरिद्वार आने वाले तीर्थयात्रियों और संतों के रहने की व्यवस्था करना और उन्हें भोजन और अन्य सुविधाएं प्रदान करना; और (ii) धार्मिक कार्य करना और आयोजित करना। याचिकाकर्ता एक संस्कृत विद्यालय के साथ-साथ एक औषधालय भी संचालित करता है।

3. स्वामी उधवदासजी महाराज दृष्टिबाधित थे। कहा जाता है कि 28 नवंबर 1955 को उन्होंने अपने चेले मोहन लाल के नाम पर हरिद्वार में दो बीघे और पचास खेवट की जमीन खरीदी थी। याचिकाकर्ता के अनुसार, स्वामी ने कच्छी लाल रामेश्वर आश्रम ट्रस्ट की स्थापना की। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने 22 अक्टूबर 1956 को कुछ व्यक्तियों को नामांकित करते हुए एक वसीयत निष्पादित की थी, जो उनके जीवनकाल के बाद संबंधित संपत्ति सहित उनकी संपत्तियों का प्रबंधन और प्रशासन करेंगे। याचिकाकर्ता के अनुसार, यह स्वामी द्वारा निष्पादित दूसरी पंजीकृत वसीयत थी, क्योंकि पहले पंजीकृत वसीयत में नामांकित लोगों में से कुछ लोग जिम्मेदारी स्वीकार करने के इच्छुक नहीं थे।

4. 13 जनवरी 1957 को स्वामी की मृत्यु हो गई। बताया जाता है कि ट्रस्ट 11 नवंबर 1957 को पंजीकृत हुआ था। ट्रस्ट के उद्देश्यों में निम्नलिखित हैं:

> "4. महराजश्रीओधवदासजी की प्रेरणा से हरिद्वार में आश्रम की स्थापना का मुख्य उद्देश्य विशेष रूप से उन कच्छी लोगों और सामान्य रूप से अन्य लोगों के लिए एक केंद्र और आश्रय प्रदान करना है, जो भक्ति और मन की शांति के

लिए हरिद्वार के पवित्र तीर्थस्थलों पर जाते हैं और यह किसी भी अन्य उद्देश्य के साथ-साथ ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य और उद्देश्य बना रहेगा जो धार्मिक शिक्षा प्रार्थना आदि जैसे मुख्य उद्देश्य को आगे बढ़ा सकता है।

5. श्रद्धेय महाराजश्री ओधवदासजी का यह प्रिय उद्देश्य था कि आश्रम को योग्य लोगों को आश्रय और भोजन दोनों प्रदान करना चाहिए और यह ट्रस्ट के निपटान में संसाधनों की सीमा के भीतर किया जा रहा है। कई लोगों ने अपने दिवंगत गुरु महाराज की इच्छानुसार "अन्ना क्षेत्र" चलाने के उद्देश्य से धन दान करने की इच्छा व्यक्त की है।

याचिकाकर्ता के मुताबिक सारी चल-अचल संपत्ति ट्रस्ट में निहित थी. 23 मार्च 1958 को, मोहन लाल द्वारा एक अपंजीकृत घोषणा निष्पादित की गई थी जिसमें कहा गया था कि यद्यपि संपत्ति उनके नाम पर स्वर्गीय स्वामी द्वारा खरीदी गई थी, लेकिन न तो उनका और न ही उनके कानूनी उत्तराधिकारियों का संपत्ति में कोई अधिकार होगा। 1958 के बाद से मोहन लाल का कोई अता-पता नहीं है.

5. 10 जुलाई 2001 को, याचिकाकर्ता द्वारा इन कार्यवाहियों के लिए वर्णित तीसरे प्रतिवादी (स्वामी महानंद अवधूत टाटाम्बरी के नाम से एक व्यक्ति) के खिलाफ निषेधाज्ञा की मांग करते हुए मुकदमा 1 स्थापित किया गया था:

"चेला स्वामी ब्रह्मचारी जी अवधूत, निवासी टाटाम्बरी आश्रम, सप्त सरोवर रोड, भूपत वाला, हरिद्वार, उत्तराखंड।"

ऐसा प्रतीत होता है कि निषेधाज्ञा का मुकदमा इस आधार पर दायर किया गया था कि तीसरा प्रतिवादी विवाद में संपत्ति के कुछ हिस्से पर निर्माण करने का प्रयास कर रहा था। मुकदमा शुरू होने के कुछ महीने बाद, तीसरे प्रतिवादी ने 15 अक्टूबर 2001 को कलेक्टर के समक्ष शिकायत दर्ज की और आरोप लगाया कि संपत्ति मोहन लाल की

है। उनके अनुसार, 28 नवंबर 1955 को गोविंद राम और शिव राम द्वारा मोहन लाल के पक्ष में एक पट्टा निष्पादित किया गया था। शिकायत के अनुसार, मोहन लाल की मृत्यु हो गई थी और कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं होने के कारण, संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1958 की धारा 29 के तहत राज्य सरकार में निहित है।

6. शिकायत मिलने के बाद कलेक्टर ने याचिकाकर्ता को नोटिस जारी किया। 13 नवंबर 2001 को कलेक्टर के समक्ष जवाब दाखिल किया गया। उत्तर में 28 नवंबर 1955 को दिवंगत स्वामी द्वारा अपने शिष्य मोहन लाल के नाम पर संपत्ति के अधिग्रहण का पता लगाया गया है और 22 नवंबर 1956 को स्वामी द्वारा निष्पादित और पंजीकृत वसीयत का उल्लेख किया गया है। जवाब 23 मार्च 1958 को मोहन लाल की घोषणा पर आधारित था जिसमें कहा गया था कि संपत्ति में उनका कोई अधिकार या हित नहीं है। जवाब में हरिद्वार विकास प्राधिकरण द्वारा योजनाओं को विधिवत मंजूरी दिए जाने के बाद कच्छी लाल रामेश्वर आश्रम ट्रस्ट द्वारा संपत्ति पर किए गए निर्माण का विज्ञापन दिया गया। उत्तर में इस तथ्य का भी उल्लेख किया गया है कि संपत्ति का ट्रस्ट के नाम पर नगरपालिका करों के लिए मूल्यांकन किया गया है। ट्रस्ट का दावा है कि उसने संपत्ति पर निर्माण किया है और पैंतालीस वर्षों तक बिना किसी रुकावट के उस पर कब्जा बनाए रखा है। इसके अलावा, यह कहा गया था कि ट्रस्ट द्वारा सिविल जज, हरिद्वार के समक्ष एक मुकदमा दायर किया गया था क्योंकि स्वामी महानंदअवधूत तातांबरी, जिन्होंने हाल ही में आसपास की संपत्ति खरीदी थी, ने कुछ अनधिकृत निर्माण किए थे जिससे ट्रस्ट के अधिकार प्रभावित हुए थे। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि इसके खिलाफ शिकायत बगल के मालिक के साथ विवाद के प्रतिशोध के रूप में कलेक्टर के समक्ष दर्ज की गई थी, जिसके कारण सिविल कोर्ट के समक्ष मुकदमा दायर किया गया था।

7. 12 मई 2003 को, हरिद्वार के कलेक्टर ने उनके द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस पर फैसला सुनाया। कलेक्टर ने माना कि संपत्ति का पट्टा मोहन लाल द्वारा 15 जुलाई 1955 और 28 नवंबर 1955 को सुरक्षित किया गया था। कलेक्टर के अनुसार, ट्रस्ट ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया था जिससे यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि संपत्ति स्वामीउधव दास के फंड से मोहन लाल के नाम पर खरीदी गई थी। कलेक्टर के अनुसार, मोहन लाल द्वारा 23 मार्च 1958 के कथित प्रवेश पत्र पर भरोसा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उसे रेहा कुच (वर्तमान में चंद्रकेला) का निवासी दिखाया गया था, जबकि जिस व्यक्ति के पक्ष में पट्टा निष्पादित किया गया था वह ग्राम ईश्वर नगर का निवासी था। कलेक्टर के अनुसार, स्वामी की मृत्यु 11 नवंबर 1957 से पहले हो गई थी। कलेक्टर की राय में, ट्रस्ट, मोहन लाल के उत्तराधिकारियों के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहा था। कलेक्टर ने मोहन लाल की मृत्यु का अनुमान लगाना शुरू कर दिया क्योंकि सात साल तक उसके बारे में कुछ नहीं सुना गया था। इस आधार पर, कलेक्टर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि संपत्ति कानून के संचालन द्वारा राज्य सरकार में निहित है। हरिद्वार के सिटी मजिस्ट्रेट को संपत्ति पर कब्जा लेने के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया।

8. कलेक्टर, हरिद्वार के आदेश से व्यथित, जिसमें माना गया कि संपत्ति हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 29 के संचालन द्वारा राज्य सरकार में निहित थी, और सिटी मजिस्ट्रेट को कब्ज़ा लेने का निर्देश दिया गया था, याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका में फैसले को चुनौती दी। ट्रन्स्ट ने पैंतालीस वर्षों से अधिक समय से संपत्ति के प्रबंधन में होने का दावा किया और प्रस्तुत किया कि वह एकमात्र नाविक है, जिसमें इसके प्रतिकूल कार्रवाई प्रशासक जनरल या सिविल कोर्ट के माध्यम से की गई स्वामित्व कार्रवाई के आधार पर की जा सकती थी। ट्रस्ट के प्रस्तुतीकरण में, कलेक्टर

उस तरीके से स्वामित्व के प्रश्न पर निर्णय लेने की शक्ति नहीं ले सकते थे जिस तरह से उन्होंने ऐसा करने का इरादा किया था।

9. मई 2003 में ट्रस्ट द्वारा उत्तराखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट कार्यवाही शुरू करने के बाद कुछ विकास हुए। तीसरे प्रतिवादी ने सिविल कोर्ट में ट्रस्ट द्वारा शुरू किए गए मुकदमे में ट्रस्ट के पक्ष में पारित अंतरिम निषेधाज्ञा के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी। . 24 दिसंबर 2003 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, हरिद्वार द्वारा अपील खारिज कर दी गई। 9 मई 2005 को, उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कलेक्टर के आदेश को चुनौती देने वाली ट्रस्ट की रिट याचिका को स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया इस आधार पर आदेश पर रोक लगा दी कि कलेक्टर के पास ऐसा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। 0 अप्रैल 2007 को, ट्रस्ट द्वारा दायर एक रिट याचिका खारिज कर दी गई (याचिकाकर्ता के अनुसार एक अन्य मामले के तथ्यों के आधार पर गलती से)। याचिकाकर्ता ने एक समीक्षा याचिका दायर की। 15 मई 2007 को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा समीक्षा की अनुमति दी गई और पहले के आदेश को वापस ले लिया गया। अंततः, 15 मई 2007 के अपने फैसले और आदेश से डिवीजन बेंच ने कलेक्टर के फैसले को बरकरार रखा।

10. उच्च न्यायालय ने माना कि 23 मार्च 1958 को मोहन लाल द्वारा निष्पादित कथित स्वीकृति विलेख एक पंजीकृत दस्तावेज नहीं है। इसके अलावा, इसमें कहा गया है कि स्वीकृति विलेख का निष्पादक मोहन लाल नाम के उस व्यक्ति से अलग व्यक्ति प्रतीत होता है जो विवादित भूमि का मालिक था। हाई कोर्ट के मुताबिक, ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे पता चले कि मोहन लाल की मृत्यु 11 नवंबर 1957 को डीड ऑफ ट्रस्ट की तैयारी से पहले हो गई थी। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि जमीन मोहन लाल द्वारा खरीदी गई थी, जिसके पक्ष में मूल पट्टे निष्पादित किए गए

थे, लेकिन यह इंगित करने के लिए कोई सबूत नहीं था कि धन स्वर्गीय स्वामी द्वारा प्रदान किया गया था। उच्च न्यायालय के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

> "10. निर्विवाद रूप से प्रश्न में भूमि मोहन लाल द्वारा 28 नवंबर 1955 और 15 जुलाई 1955 के पट्टों के माध्यम से खरीदी गई थी, जबकि अपीलकर्ता का दावा है कि भूमि महंत उधव दास द्वारा मोहन लाल के नाम पर खरीदी गई थी लेकिन अपीलकर्ता की ओर से ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया है जिससे पता चले कि जमीन महंत उधवदास जी के पैसे से खरीदी गई थी। अपीलकर्ता यह स्थापित नहीं कर पाया है कि मोहन लाल जिसके नाम पर जमीन खरीदी गई थी और मोहन लाल जिसने स्वीकृति विलेख निष्पादित किया था, एक ही व्यक्ति हैं। अपीलकर्ता ट्रस्ट ने खुद को विवादित संपत्ति के मालिक मोहनलाल का कानूनी उत्तराधिकारी होने का दावा नहीं किया है, लेकिन उसने 22 अक्टूबर 1956 की वसीयत के आधार पर स्वामित्व का दावा किया है, जिसे मोहन लाल ने निष्पादित नहीं किया था। भूमि के मालिक, मोहन लाल का कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, इसलिए, विवादित भूमि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 29 के प्रावधान के मद्देनजर राज्य सरकार को हस्तांतरित की जानी थी। हमें इस मामले में कलेक्टर द्वारा पारित आदेश में कोई खामी नहीं मिली ह" ।

11. इन कार्यवाहियों में 12 मई 2009 को यथास्थिति का आदेश जारी होने पर अनुमति दी गई थी।

12. अपीलकर्ताओं की ओर से, यह श्री आर्यमा सुंदरम, विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि:

(i) कलेक्टर ने सिविल कोर्ट की शक्तियों को संभालने और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 29 के तहत संपत्ति को राज्य में निहित करने पर निर्णय देने में, अधिकार क्षेत्र के बिना कार्य किया है;

(ii) स्पष्ट विवाद को ध्यान में रखते हुए, जिसमें प्रतिद्वंद्वी शीर्षकों की स्थापना शामिल है- सरकार सेक्टर 29 के तहत दावा कर रही है और ट्रस्ट एक विपरीत शीर्षक स्थापित कर रहा है, यह कलेक्टर के लिए राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपनी क्षमता में अपने मामले में न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए खुला नहीं था; ·

(iii) जहां शीर्षक का विवाद या धारा 29 के अर्थ के भीतर कानूनी उत्तराधिकारियों की अनुपस्थिति के संबंध में विवाद उठता है, केवल एक सिविल अदालत ही क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकती है; और

(iv) यह मानते हुए कि संपत्ति मोहन लाल की थी, कलेक्टर को उन्हें उचित सूचना दिए बिना मामले में आगे नहीं बढ़ना चाहिए था और इसलिए यह निष्कर्ष गलत है कि मोहन लाल मर चुके थे, क्योंकि सात साल तक उनके बारे में कुछ नहीं सुना गया।

13. दूसरी ओर, राज्य सरकार की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि कलेक्टर द्वारा पारित आदेश क्षेत्राधिकार का एक वैध अभ्यास है। यह आग्रह किया गया था कि कलेक्टर उचित रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि मोहन लाल का उत्तराधिकारी कोई नहीं था, जिस पर संपत्ति को हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 29 के तहत राज्य में निहित माना जाना चाहिए। यह ध्यान दिया जा सकता है कि इन कार्यवाही में जो जवाबी हलफनामा पेश किया गया है, उसमें पहले और दूसरे उत्तरदाताओं ने कहा है कि कलेक्टर की शक्ति का स्रोत हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 29 से पता लगाया जा सकता है, इसके अलावा उत्तराखंड राज्य में इसके आवेदन में उत्तर

प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 167 (2) पर भरोसा जताया गया है।

14. तीसरे प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एमएन राव ने उस प्रस्तुतिकरण को स्वीकार कर लिया है, जिसका आग्रह उनके मुवक्किल ने शिकायतकर्ता के रूप में कलेक्टर के समक्ष किया था। विद्वान वरिष्ठ वकील ने हालांकि आग्रह किया कि जो आदेश पारित किया गया है उसे बरकरार रखना कलेक्टर और राज्य का काम है।

15. इससे पहले कि हम प्रतिद्वंद्वी विवादों के गुणों से निपटें, किसी मुद्दे को दहलीज पर संबोधित करने की आवश्यकता है। प्रारंभ में, 16 जुलाई 2007 को, नोटिस "इस सवाल तक सीमित था कि क्या कलेक्टर को प्रशासक-सामान्य अधिनियम, 1963 के प्रावधानों के मद्देनजर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 29 के तहत आदेश पारित करने की शक्ति थी। ". अनुमति 12 मई 2009 को दी गई थी। प्रारंभिक आदेश पर भरोसा करते हुए, जिसने नोटिस को एक विशिष्ट मुद्दे तक सीमित कर दिया था, राज्य के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बाद में छुट्टी देने को अपील में उठाए गए सभी मुद्दों पर विवाद का दायरा बढ़ाने वाला नहीं माना जाना चाहिए। इसलिए, निवेदन यह है कि एकमात्र मुद्दा जिसे संबोधित किया जाना चाहिए वह वह है जिसे नोटिस जारी करते समय विज्ञापित किया गया था।

16. प्रारंभिक मुद्दे को संबोधित करते समय, हमारे विचार में, एक व्यापक सामान्यीकरण निर्धारित करना अनुचित और, शायद असुरक्षित भी होगा। इस न्यायालय को जो संवैधानिक क्षेत्राधिकार प्रदान किया गया है उसका आधार न्याय की उन्नति है। न्याय प्रदान करने की अदालत की शक्ति को उसके अधिदेश के प्रति संकीर्ण दृष्टिकोण द्वारा सीमित नहीं किया जाना चाहिए। एक आपराधिक मामले के संदर्भ में, योमेशभाई प्राणशंकर भट्ट बनाम गुजरात राज्य मामले में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की

पीठ ने एक ऐसी स्थिति पर विचार किया जहां उच्च न्यायालय द्वारा दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि की पुष्टि की गई थी। प्रारंभ में, इस न्यायालय ने केवल इस प्रश्न तक ही सीमित नोटिस जारी किया कि क्या अभियुक्त धारा 304 के किसी भी भाग के तहत अपराध करने का दोषी था, न कि धारा 302 के तहत। मुद्दा यह था कि क्या अपील का दायरा शुरू में जारी नोटिस में कही गई बातों तक ही सीमित था। इस संदर्भ में, न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट नियम, 1966 का हवाला दिया, जो संविधान के अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए हैं। इस न्यायालय की प्रक्रिया के नियमों का आदेश XLVII नियम 6 निम्नानुसार प्रदान करता है:

> "6. इन नियमों में कुछ भी ऐसे आदेश देने के लिए न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या अन्यथा प्रभावित करने वाला नहीं माना जाएगा जो न्याय के लिए या न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यक हो सकते हैं।"

संविधान का अनुच्छेद 142 इस न्यायालय को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित करने और ऐसे आदेश देने में सक्षम बनाता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक है। अनुच्छेद 142 को विज्ञापित करने के बाद, इस न्यायालय ने इस प्रकार कहा:

> "18. इसलिए, यह स्पष्ट है कि न्यायालय मामले की अंतिम सुनवाई करते समय और मामले के न्याय पर विचार करते हुए ऐसे आदेश पारित कर सकता है जो मामले के न्याय की मांग है और ऐसा करते समय, इसके विपरीत कानून के किसी भी स्पष्ट प्रावधान को छोड़कर न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर कोई बंधन नहीं लगाया गया है, और आम तौर पर यह न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत

अपनी शक्ति का प्रयोग करते समय इसे अनदेखा नहीं कर सकता है। किसी याचिका को स्वीकार करते समय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को जबड़े के स्पष्ट प्रावधान की स्थिति नहीं प्राप्त होती है। किसी याचिका पर विचार करते समय नोटिस जारी करते समय न्यायालय द्वारा की गई कोई भी टिप्पणी अस्थायी टिप्पणी होती है। वे टिप्पणियाँ या आदेश अनुच्छेद 142 के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को सीमित नहीं कर सकते।"

इसलिए, न्यायालय ने कहा कि अंतिम सुनवाई के समय, उसे "संपूर्ण परिप्रेक्ष्य में" विवाद पर विचार करने से रोका नहीं जाएगा और ऐसा करते समय, वह "किसी भी अवलोकन से बाधित नहीं होगा।" नोटिस जारी करते समय किया गया कोई भी आदेश।''उत्तराखंड राज्य बनाम आलोक शर्मा' मामले में पहले के फैसले में इसी तरह का दृष्टिकोण लिया गया था। इंडियन बैंक बनाम गोधरा नागरिक सहकारी क्रेडिट सोसाइटी लिमिटेड में इस न्यायालय के दो न्यायाधीशों की एक पीठ ने कहा था कि हालाँकि शुरू में एक सीमित नोटिस जारी किया गया था, लेकिन उसके बाद अनुमति दे दी गई, "पार्टियों के सभी विवाद अब खुले हैं"।

17. हम इस दृष्टिकोण का सम्मानपूर्वक दोहराते हैं और इसे अपनाते हैं जो न्यायालय को प्रदत्त संवैधानिक शक्तियों के प्रति एक बुद्धिमान दृष्टिकोण पर आधारित है। अनुच्छेद 142 इस मौलिक सिद्धांत का प्रतीक है कि न्यायालय का अधिकार क्षेत्र पूर्ण न्याय प्रदान करना है और इसकी एक घटना के रूप में, न्यायालय ऐसे डिक्री या आदेश पारित कर सकता है जैसा वह उचित समझे। जब अदालत शुरू में एक सीमित नोटिस जारी करती है लेकिन बाद में अनुदान छोड़ देती है, तो अपील का दायरा अधिकार क्षेत्र का नहीं बल्कि न्यायिक विवेक का मामला उठाता है। चूंकि यह विवेक का मामला है न कि अधिकार क्षेत्र का, इसलिए मार्गदर्शक सिद्धांत पर्याप्त न्याय की उन्नति होना चाहिए।

18. कलेक्टर द्वारा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 29 लागू की गई है। धारा 29 इस प्रकार प्रदान करती है:

> "29. उत्तराधिकारियों की विफलता- यदि किसी निर्वसीयतकर्ता ने इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपनी संपत्ति के उत्तराधिकारी के लिए कोई योग्य उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा है, ऐसी संपत्ति सरकार को हस्तांतरित हो जाएगी और सरकार संपत्ति को उन सभी दायित्वों और देनदारियों के अधीन ले लेगी, जिनके अधीन एक उत्तराधिकारी होगा।"

धारा 29 राजद्रोह के सिद्धांत का प्रतीक है। राजद्रोह का सिद्धांत यह मानता है कि जहां कोई व्यक्ति बिना वसीयत किए मर जाता है और अपने पीछे कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ता जो संपत्ति का उत्तराधिकारी होने के योग्य हो, तो संपत्ति सरकार को हस्तांतरित हो जाती है। हालाँकि ऐसी स्थिति में संपत्ति सरकार को हस्तांतरित हो जाती है, फिर भी सरकार इसे अपने सभी दायित्वों और देनदारियों के अधीन लेती है, दूसरे शब्दों में, राज्य संपत्ति को "मृतक के प्रतिद्वंद्वी या अधिमान्य उत्तराधिकारी के रूप में नहीं बल्कि देश की पूरी धरती के सर्वोपरि स्वामी के रूप में लेता है", जैसा कि पंजाब राज्य बनाम बलवंत सिंह5 में हुआ था। इंग्लैंड के हैल्सबरी के कानूनों के इस सिद्धांत को धारा 29 के दायरे को समझाते समय इस न्यायालय द्वारा अपनाया गया था। धारा 29 केवल उत्तराधिकारियों के असफल होने पर ही लागू होती है। विफलता का अर्थ है बिना वसीयत के मरने वाले व्यक्ति के किसी भी उत्तराधिकारी की पूर्ण अनुपस्थिति। जब राजद्रोह का प्रश्न उठता है, तो जिम्मेदारी बहुत हद तक उस व्यक्ति पर होती है जो मामले को स्थापित करने के लिए उस व्यक्ति की संपत्ति पर उत्तराधिकार के लिए योग्य उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति का दावा करता है जो बिना वसीयत के मर गया है। कानून ऐसे परिणाम को आसानी से स्वीकार नहीं करता। बिहार राज्य राधा कृष्ण

सिंह 7 में, इस न्यायालय के तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणियों में सिद्धांत तैयार किया:

"272. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब सरकार द्वारा धोखाधड़ी का दावा पेश किया जाता है तो दुनिया में कहीं भी प्रतिवादी के किसी भी उत्तराधिकारी की अनुपस्थिति को साबित करने की जिम्मेदारी अपीलकर्ता पर होती है। आम तौर पर, जब तक कि राजद्रोह के लिए आवश्यक शर्तें पूरी तरह से और पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हो जातीं, तब तक अदालत संपत्ति को धोखे से ले जाने पर नाराजगी व्यक्त करती है। इसके अलावा, धोखाधड़ी की याचिका पर विचार करने से पहले, सरकार द्वारा एक सार्वजनिक नोटिस दिया जाना चाहिए ताकि यदि देश में या दुनिया में कहीं भी उस मामले के लिए कोई दावेदार हो, तो वह राज्य के दावे का मुकाबला करने के लिए आगे आ सके। . वर्तमान मामले में, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों ने केवल वादी-प्रतिवादियों के दावों का विरोध करके खुद को संतुष्ट किया। भले ही वे यह दिखाने में सफल हो जाएं कि वादी दिवंगत महाराज ए के निकटतम प्रतिवादी नहीं थे, फिर भी यह तार्किक परिणाम नहीं है कि वादी के दावे की विफलता से यह अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकलेगा कि कोई अन्य उत्तराधिकारी नहीं है जो किसी भी समय संपत्तियों पर दावा करने के लिए आगे आ सके।" {पृ. 216 पर आईडी)

मुल्ला का हिंदू कानून इस स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत करता है:

"जहां राजमुकुट या सरकार राजद्रोह द्वारा दावा करती है, वहां यह दिखाने की जिम्मेदारी उस पर होती है कि संपत्ति का मालिक बिना किसी वारिस के मर गया। राजद्रोह द्वारा ली गई संपत्ति पहले से संपत्ति को प्रभावित करने वाले ट्रस्टों,

आरोपों और कानूनी दायित्वों (यदि कोई हो) के अधीन है , उदाहरण के लिए, बंधक और अन्य ऋणभार। इस धारा का नियम है कि अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त सभी उत्तराधिकारियों की विफलता की स्थिति में, बिना वसीयत के मालिक की मृत्यु पर, उसकी संपत्ति सरकार को हस्तांतरित हो जाती है। सरकार संपत्ति को उन सभी कानूनी दायित्वों और देनदारियों के अधीन रखती है जिनके अधीन एक उत्तराधिकारी होता यदि संपत्ति उत्तराधिकार द्वारा वारिस को हस्तांतरित की गई होती। अनुभाग में प्रयुक्त 'विफलता' शब्द बहुत प्रिय है और इस तथ्य का सूचक है कि निर्वसीयत के उत्तराधिकारियों का अभाव होना चाहिए।"

रामबीर दास बनाम कल्याण दास 9 में, इस न्यायालय के दो विद्वान न्यायाधीशों की एक पीठ ने शेबेटशिप के एक मामले की सुनवाई की। न्यायमूर्ति बीके मुखर्जी के प्रसिद्ध टैगोर लॉ व्याख्यान के अधिकार का अनुमोदन के साथ हवाला देते हुए, इस न्यायालय ने व्याख्यान में स्पष्ट कानून की स्थिति पर ध्यान दिया:

"चूंकि शेबेटशिप संपत्ति है, यह विरासत के सामान्य हिंदू कानून के अनुसार किसी भी अन्य संपत्ति की तरह हस्तांतरित होती है। यदि यह संस्थापक में बनी रहती है, तो यह संस्थापक के उत्तराधिकारियों की पंक्ति का अनुसरण करती है; फिट का निपटान पूरी तरह से अनुदान प्राप्तकर्ता के पक्ष में किया जाता है, यह सामान्य तरीके से उत्तरार्द्ध के उत्तराधिकारियों को हस्तांतरित होता है और यदि किसी कारण से दाता द्वारा नियुक्त रेखा पूरी तरह से विफल हो जाती है, तो शेबेटशिप संस्थापक के परिवार में वापस आ जाती है।

भागने के सवाल पर, न्यायमूर्ति बी के मुखर्जी इस प्रकार कहते हैं:

"जैसा कि हमेशा संस्थापक या उसके उत्तराधिकारियों के प्रति अंतिम प्रतिगमन होता है, यदि शेबैट्स की वंशावली विलुप्त हो जाती है, तो जहां तक शेबेटशिप के हस्तांतरण का संबंध है, सख्ती से पलायन का कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन मामलों की कल्पना की जा सकती है, जहां संस्थापक ने कोई उत्तराधिकारी नहीं छोड़ा है, और ऐसे मामलों में संस्थापक की संपत्तियां संपन्न संपत्ति के साथ राज्य में स्थानांतरित हो सकती हैं। ऐसी परिस्थितियों में, राज्य के अधिकार संभवतः संस्थापक के समान ही होंगे, और उसे पहली संपत्ति के लिए शेबेट नियुक्त करना होगा। यह नहीं कहा जा सकता है कि राजद्रोह द्वारा समर्पित संपत्ति प्राप्त करने वाला राज्य ट्रस्ट को समाप्त कर सकता है और इसे धर्मनिरपेक्ष संपत्ति के रूप में मान सकता है।"

दूसरे शब्दों में, यहां तक कि ऐसी स्थिति में भी जहां एक संस्थापक या उसके उत्तराधिकारियों की पंक्ति विलुप्त हो गई है, और संपत्तियां राज्य के पास चली जाती हैं, राज्य जो एक समर्पित संपत्ति प्राप्त करता है वह ट्रस्ट के अधीन है और इसे धर्मनिरपेक्ष संपत्ति के रूप में व्यवहार नहीं कर सकता है। वास्तव में, हम ध्यान दे सकते हैं, धारा 29 स्पष्ट रूप से निर्धारित करती है कि राज्य "संपत्ति को उन सभी दायित्वों और देनदारियों के अधीन ले लेगा जिनके अधीन एक उत्तराधिकारी होता।"

19. इस मामले का निर्णय करते समय, इस न्यायालय को स्थापित सिद्धांत को भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब तक किसी गणित या धार्मिक संस्थान के संस्थापक ने बंदोबस्ती के उत्तराधिकार को नियंत्रित करने वाले सिद्धांत को निर्धारित नहीं किया है, उत्तराधिकार को संस्था के रीति-रिवाज या उपयोग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह सिद्धांत छह दशक पहले इस न्यायालय द्वारा महंत सीता दास बनाम संत राम 10 में प्रतिपादित किया गया था, जिसका प्रतिपादन न्यायमूर्ति बीके मुखर्जी ने चार न्यायाधीशों की पीठ के लिए बोलते हुए किया था:

"10. हमारे समक्ष अपील में पार्टियों द्वारा उठाए गए तर्क मुख्य रूप से इस बिंदु पर केंद्रित हैं कि क्या किशोर दास की मृत्यु के बाद, वादी या प्रतिवादी 3 ने विवाद में ठाकरद्वारे के संबंध में महंत के अधिकार हासिल कर लिए हैं। कानून अच्छी तरह से तय है कि किसी मठ या धार्मिक संस्थान के महंत पद का उत्तराधिकार उस विशेष संस्थान के रीति-रिवाज या उपयोग द्वारा नियंत्रित होता है, सिवाय इसके कि उत्तराधिकार का नियम संस्थापक द्वारा स्वयं निर्धारित किया जाता है जिसने बंदोबस्ती बनाई थी। जैसा कि न्यायिक समिति ने इस बिंदु पर कई मामलों में से एक में गेंदापुरी बनाम छतरपुरी, 13 जेए100, एल 05] में निर्धारित किया था; "यह निर्धारित करने में कि मोहंट के रूप में सफल होने का हकदार कौन है, पालन किया जाने वाला एकमात्र कानून रीति-रिवाज और अभ्यास में पाया जाना है, जिसे गवाही द्वारा साबित किया जाना चाहिए, और दावेदार को यह दिखाना होगा कि प्रथा के अनुसार वह कार्यालय और उससे संबंधित भूमि और संपत्ति को पुनः प्राप्त करने का हकदार है... .. प्रतिवादी, जो कब्जे में है, के स्वामित्व की मात्र दुर्बलता से वादी को मदद नहीं मिलेगी।'

20. मूल मुद्दा जिसे उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में संबोधित किया जाना है, वह यह है कि क्या कलेक्टर के पास खुद को एक न्यायिक मंच की शक्ति मानकर स्वामित्व के प्रश्न पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र था। कलेक्टर का आदेश इंगित करता है कि यह मुद्दा कि क्या धारा 29 के अर्थ के तहत उत्तराधिकारियों की विफलता के परिणामस्वरूप संपत्ति राज्य सरकार में निहित होगी, एक गंभीर रूप से विवादित मुद्दा था जो परस्पर विरोधी दावों के निर्णय पर आधारित था। कथित तौर पर धारा 29 के तहत मुद्दे को निर्धारित करने की प्रक्रिया में, कलेक्टर ने विभिन्न तथ्यात्मक मामलों पर फैसला सुनाया है, जिसमें (i) क्या संपत्ति 1955 में मोहन लाल द्वारा स्वामीउधव दास द्वारा प्रदान की गई धनराशि से खरीदी गई थी; (ii) पंजीकृत वसीयत की वैधता को स्वामी

द्वारा 22 अक्टूबर 1956 को निष्पादित किया गया बताया गया है; (iii) उस व्यक्ति की पहचान जिसने 23 मार्च 1958 को स्वीकृति विलेख निष्पादित किया था, उस व्यक्ति की तुलना में जिसके नाम पर 1955 में पट्टा प्राप्त किया गया था; (iv) क्या मोहन लाल की मृत्यु 11 नवंबर 1957 को ट्रस्ट के विलेख के निष्पादन से पहले हो गई थी; और (v) क्या मोहन लाल की मृत्यु के संबंध में कोई धारणा कथित तौर पर सात वर्षों तक उसकी सुनवाई नहीं होने पर उत्पन्न होगी। कलेक्टर अन्य तथ्यात्मक मुद्दों के अलावा, इन पर निर्णय लेने के लिए आगे बढ़े हैं। धारा 29, यह ध्यान दिया जा सकता है, एक सिद्धांत का प्रतीक है लेकिन विवादित प्रश्नों पर निर्णय के लिए एक प्रक्रियात्मक तंत्र प्रदान नहीं करता है। न्यायालय के समक्ष विवाद का कैनवास उन मामलों का प्रचुर संकेत है जो गंभीर रूप से विवाद में थे। राज्य का तर्क है कि मोहन लाल को मृत मान लेने के परिणामस्वरूप संपत्ति उसे हस्तांतरित हो जाएगी और अपने पीछे कोई कानूनी उत्तराधिकारी न छोड़ना गंभीर रूप से सवालों के घेरे में है। इस तरह के मामले पर कलेक्टर द्वारा खुद को ऐसा अधिकार क्षेत्र मानकर निर्णय नहीं दिया जा सकता था जो उन्हें कानून द्वारा प्रदान नहीं किया गया है।

21. यह सिद्धांत कि कानून आसानी से भागने के दावे को स्वीकार नहीं करता है और जिम्मेदारी उस व्यक्ति पर बहुत अधिक है जो यह दावा करता है कि एक व्यक्ति की बिना वसीयत के मृत्यु हो गई है, जिससे संपत्ति पर उत्तराधिकार के लिए योग्य कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं बचा है, यह एक ठोस आधार पर आधारित है। तर्क. एस्केट एक सिद्धांत है जो राज्य को एक सर्वोपरि संप्रभु के रूप में मान्यता देता है जिसमें संपत्ति केवल उत्तराधिकारियों की विफलता के स्पष्ट और स्थापित मामले पर ही निहित होगी। यह सिद्धांत इस मानदंड पर आधारित है कि कानून के शासन द्वारा शासित समाज में, अदालत यह नहीं मानेगी कि निजी स्वामित्व राज्य के पक्ष में अधिरोहित हैं, शासी वैधानिक प्रावधान के आधार पर कोई स्पष्ट मामला न होने की स्थिति में। राज्य के प्रशासनिक अधिकारियों- जिनमें कलेक्टर भी शामिल है, जैसा कि वर्तमान मामले में

है- को नागरिक विवादों से जुड़े स्वामित्व के मामलों पर निर्णय लेने की अनुमति देना कानून के शासन के लिए विनाशकारी होगा। कलेक्टर राज्य का एक अधिकारी होता है। वह केवल उन्हीं शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जो कानून उसे निजी विवादों में प्रवेश करने के लिए विशेष रूप से प्रदान करता है। इसके विपरीत, एक सिविल न्यायालय के पास नागरिक विवादों से जुड़े सभी मामलों पर निर्णय लेने का अधिकार क्षेत्र होता है, सिवाय इसके कि जहां न्यायालय का अधिकार क्षेत्र छीन लिया गया हो; या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा, क़ानून द्वारा। यह मानते हुए कि कलेक्टर ने वर्तमान मामले में अधिकार क्षेत्र के बिना काम किया है, अदालत के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह संपत्ति पर याचिकाकर्ता द्वारा दावा किए गए शीर्षक को मान्य करने के लिए आगे बढ़े। अदालत को यह तय करने के लिए नहीं बुलाया गया है कि पैंतालीस साल से अधिक समय से ट्रस्ट द्वारा दावा किया गया कब्ज़ा एक विश्वसनीय शीर्षक द्वारा समर्थित है या नहीं। आवश्यक बात यह है कि इस तरह का न्यायिक कार्य कलेक्टर द्वारा अपने ऊपर नहीं थोपा जा सकता था। उपाधियों पर निर्णय के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 9 के तहत सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के सामान्य नागरिक-न्यायालय का सहारा लेना चाहिए।

22. इस स्तर पर हम प्रशासक-सामान्य अधिनियम, 1963 के प्रावधानों का भी विज्ञापन कर सकते हैं। अधिनियम उन व्यक्तियों की नियुक्ति का प्रावधान करता है जिनके पास प्रशासक जनरल की शक्तियां निहित हैं। धारा 2(ए) अभिव्यक्ति 'संपत्ति' को इस प्रकार परिभाषित करती है:

"(ए) "संपत्ति" का अर्थ है मृत व्यक्ति की सभी चल और अचल संपत्ति, जो उसके ऋणों और विरासतों के भुगतान के लिए प्रभार्य और लागू होती है, या उसके उत्तराधिकारियों और निकटतम रिश्तेदारों के बीच वितरण के लिए उपलब्ध होती है"।

प्रशासक जनरल को धारा 3 के तहत अधिसूचित किया जाता है।

धारा 7 उच्च न्यायालय द्वारा राज्य के प्रशासक जनरल को प्रशासन पत्र देने की अनुमति देती है, जब तक कि वे मृतक के निकटतम रिश्तेदार को नहीं दिए जाते। धारा 7 इस प्रकार है:

> "7. प्रशासक-जनरल प्रशासन पत्रों का हकदार है, जब तक कि यह निकटतम रिश्तेदार को न दिया गया हो:- उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए प्रशासन के कोई भी पत्र राज्य के प्रशासक-जनरल को दिए जाएंगे, जब तक कि वे मृतक के निकटतम रिश्तेदार को नहीं दिए जाते।"

धारा 9 प्रशासक जनरल को निर्दिष्ट परिस्थितियों में सम्पदा के प्रशासन के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार देती है: ,

> "9. सम्पदा के प्रशासन के लिए आवेदन करने का प्रशासक-जनरल का अधिकार:-
>
> (1) यदि- (ए) किसी भी व्यक्ति की मृत्यु किसी भी राज्य में दस लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति छोड़कर हुई है, और
>
> (बी) क्या उसकी वसीयत या उसकी संपत्ति के प्रशासन पत्र की प्रोबेट प्राप्त करना अनिवार्य है या नहीं, कोई भी व्यक्ति जिसे किसी भी न्यायालय के पास ऐसी संपत्तियों का प्रशासन सौंपने का अधिकार क्षेत्र होगा, उसने अपनी मृत्यु के एक महीने के भीतर, ऐसे राज्य में ऐसी प्रोबेट, या प्रशासन पत्र के लिए आवेदन नहीं किया है, और
>
> (सी) ऐसे मामलों में जहां भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधानों के तहत ऐसी प्रोबेट या प्रशासन पत्र प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है), किसी भी

व्यक्ति ने राज्य के प्रशासक-जनरल, संपत्ति की सुरक्षा के लिए अन्य कार्यवाही नहीं की है, जिसमें ऐसी संपत्तियां, राज्य सरकार द्वारा बनाए गए किसी भी नियम के अधीन, ऐसे व्यक्ति की मृत्यु की सूचना मिलने के बाद उचित समय के भीतर, और उसके द्वारा ऐसी संपत्तियों को छोड़ने की हो सकती हैं, ऐसी कार्यवाही करना जो उच्च न्यायालय से ऐसे व्यक्ति की संपत्ति के प्रशासन पत्र प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो।

(2) प्रशासक-जनरल इस धारा के तहत तब तक कार्यवाही नहीं करेगा जब तक वह संतुष्ट न हो जाए, यदि उसके द्वारा ऐसी कार्यवाही नहीं की जाती है तो ऐसी परिसंपत्तियों के दुरुपयोग, गिरावट या बर्बादी की आशंका है या परिसंपत्तियों की सुरक्षा के लिए ऐसी कार्यवाही आवश्यक है।"

प्रशासक जनरल को वैधानिक रूप से किसी मृतक की संपत्ति या संपदा को बर्बादी से बचाने के लिए उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार है।

धारा 10 एडमिनिस्ट्रेटर जनरल को मृत व्यक्ति की संपत्ति इकट्ठा करने और उस पर कब्जा करने के लिए उच्च न्यायालय में जाने का अधिकार देती है, जहां संपत्ति के दुरुपयोग, गिरावट या बर्बादी का आसन्न खतरा हो:

"10. जहां तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो वहां संपत्ति एकत्र करने और रखने की प्रशासक-जनरल की शक्ति:-

(1) जब भी कोई व्यक्ति किसी राज्य के भीतर दस लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति छोड़कर मर गया है, और उस राज्य का उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि ऐसी संपत्ति के दुरुपयोग, गिरावट या बर्बादी का आसन्न खतरा है, तो तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, उच्च न्यायालय, प्रशासक-जनरल या ऐसी

संपत्तियों में या उसके उचित प्रशासन में रुचि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के आवेदन पर, प्रशासक-जनरल को तुरंत निर्देश दे सकता है

- (ए) ऐसी संपत्तियों को इकट्ठा करने और कब्जा लेने के लिए, और (बी) उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इसे धारण करना, जमा करना, वसूली करना, बेचना या निवेश करना, और ऐसे किसी भी निर्देश के डिफ़ॉल्ट होने पर, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, जहां तक यह ऐसी परिसंपत्तियों पर लागू होता है।

(2)उपधारा (1) के तहत हाई कॉलि.आरटी का कोई भी आदेश एडमिनिस्ट्रेटर जनरल को हकदार बनाएगा

(ए) ऐसी संपत्तियों की वसूली के लिए कोई मुकदमा या कार्यवाही बनाए रखना;

(बी) यदि वह उचित समझता है, तो ऐसे मृत व्यक्ति की संपत्ति के प्रशासन पत्र के लिए आवेदन करना;

'(सी) इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के तहत प्रभार्य किसी भी शुल्क को संपत्ति की संपत्ति से बाहर रखने के लिए'; और

(डी) ऐसी परिसंपत्तियों के संबंध में उसके द्वारा किए गए सभी भुगतानों की प्रतिपूर्ति स्वयं करना, जो एक निजी प्रशासक ने कानूनी रूप से किया हो।

धारा 11 के तहत, उच्च न्यायालय को किसी अन्य व्यक्ति को प्रोबेट या पत्र प्रशासन देने का अधिकार है जो उपस्थित होता है और अपना दावा स्थापित करता है:

11. प्रशासक-जनरल द्वारा की गई कार्यवाही के दौरान उपस्थित होने वाले व्यक्ति को प्रोबेट या प्रशासन पत्र प्रदान करना:- यदि, धारा 9 या धारा 10 के प्रावधानों के तहत प्रशासन पत्र प्राप्त करने की कार्यवाही के दौरान, -

(ए) कोई भी व्यक्ति उपस्थित होता है और अपना दावा स्थापित करता है-

(i) मृतक की वसीयत की प्रोबेट करना; या

(ii) मृतक के निकटतम रिश्तेदार के रूप में प्रशासन के पत्रों को, और ऐसी सुरक्षा देता है जो कानून द्वारा उससे अपेक्षित हो सकती है; या

(बी) कोई भी व्यक्ति उच्च न्यायालय को संतुष्ट करता है कि उसने संपत्ति की सुरक्षा के लिए अन्य कार्यवाही की है और उचित परिश्रम के साथ मुकदमा चला रहा है,

ऐसा मामला जिसमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (39/1925) के प्रावधानों के तहत ऐसी प्रोबेट या प्रशासन पत्र प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है; या

(सी) उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि संपत्ति के दुरुपयोग, गिरावट या बर्बादी की कोई आशंका नहीं है और ऐसी कार्यवाही में प्रशासन पत्र देना संपत्ति की सुरक्षा के लिए अन्यथा आवश्यक नहीं है; उच्च न्यायालय करेगा -

(I) खंड (ए) में उल्लिखित मामले में, तदनुसार वसीयत या प्रशासन पत्र का प्रोबेट प्रदान करें;

(2) खंड (बी) या (खंड (सी) में उल्लिखित मामले में, कार्यवाही बंद करें; और

.

(3) सभी मामलों में प्रशासक-जनरल को उन धाराओं के तहत उसके द्वारा की गई किसी भी कार्यवाही की लागत का भुगतान वसीयत या गैर-वसीयत खर्च के हिस्से के रूप में संपत्ति से किया जाएगा।

धारा 12 उन घटनाओं को दर्शाती है जिनमें प्रशासक जनरल को प्रशासन दिया जा सकता है:

"12; कुछ मामलों में प्रशासक-जनरल को प्रशासन प्रदान करना :- यदि, कार्यवाही के दौरान धारा 9 या धारा 10 के प्रावधानों के तहत और ऐसी अवधि के भीतर प्रशासन के पत्र प्राप्त करना उच्च न्यायालय के लिए उचित लगता है, कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है और वसीयत की प्रोबेट, या मृतक के निकटतम रिश्तेदार के रूप में प्रशासन पत्र देने के लिए अपना दावा स्थापित नहीं करता है, या उच्च न्यायालय को संतुष्ट नहीं करता है कि उसने संपत्ति की सुरक्षा के लिए अन्य कार्यवाही उचित परिश्रम के साथ की है और कर रहा है, ऐसा मामला जिसमें भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 (39of1925) के प्रावधानों के तहत ऐसी प्रोबेट या प्रशासन पत्र प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है; और उच्च न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि संपत्तियों के दुरुपयोग, गिरावट या बर्बादी की आशंका है या ऐसी कार्यवाहियों में प्रशासन पत्र देना अन्यथा संपत्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक है; या यदि कोई व्यक्ति जिसने मृतक के निकटतम रिश्तेदार के रूप में प्रशासन के पत्र देने के लिए अपना दावा स्थापित किया है, वह ऐसी सुरक्षा देने में विफल रहता है जो कानून द्वारा उससे अपेक्षित हो सकती है; 'उच्च न्यायालय प्रशासक-जनरल को प्रशासन पत्र प्रदान कर सकता है।"

धारा 14 के तहत, प्रशासक जनरल को प्रशासन पत्र का अनुदान रद्द किया जा सकता है, जहां निष्पादक या मृतक का निकटतम संबंधी प्रशासक जनरल की प्राथमिकता में प्रोबेट या प्रशासन पत्र के लिए दावा स्थापित करता है:

"14. प्रशासक-जनरल के प्रशासन को वापस लेना और निष्पादक या निकटतम रिश्तेदार को प्रोबेट आदि देना:- यदि कोई निष्पादक या मृतक का निकटतम

रिश्तेदार, जिसे व्यक्तिगत रूप से प्रशस्ति पत्र नहीं दिया गया है या जिसे उसके पास उसके अनुसरण में उपस्थित होने के लिए समय पर नोटिस नहीं है, उच्च न्यायालय की संतुष्टि के लिए प्रशासक की प्राथमिकता में वसीयत या प्रशासन के पत्रों की प्रोबेट का दावा स्थापित करता है-सामान्य, इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रशासक जनरल को दिया गया कोई भी प्रशासन पत्र:

(ए) रद्द कर दिया जाएगा, यदि मृतक की वसीयत राज्य में साबित हो जाती है; (बी) अन्य मामलों में रद्द किया जा सकता है, यदि उस उद्देश्य के लिए आवेदन प्रशासक-जनरल को अनुदान के छह महीने के भीतर किया जाता है और उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि आवेदन करने में कोई अनुचित देरी नहीं हुई है, या उस प्राधिकारी को प्रेषित करना जिसके तहत आवेदन किया गया है; और प्रोबेट या प्रशासन पत्र ऐसे निष्पादक या निकटतम रिश्तेदार को, जैसा भी मामला हो, दिया जा सकता है।"

प्रोबेट या प्रशासन पत्र देने का प्रभाव धारा 20(1) द्वारा प्रदान किया जाता है जो इस प्रकार है:

"20. प्रशासक-जनरल को दी गई प्रोबेट या पत्रों का प्रभाव:- (1) किसी भी राज्य के प्रशासक-जनरल को उच्च न्यायालय द्वारा दी गई प्रोबेट या प्रशासन पत्रों का पूरे भारत में मृतक की सभी संपत्तियों पर प्रभाव पड़ेगा और मृतक के सभी देनदारों और ऐसी संपत्ति रखने वाले सभी व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिनिधि शीर्षक के बारे में निर्णायक होगा, और अपने ऋण का भुगतान करने वाले सभी देनदारों और ऐसे प्रशासक-जनरल को ऐसी संपत्ति सौंपने वाले सभी व्यक्तियों को पूर्ण क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा।"

23. संसद द्वारा अधिनियमित उपरोक्त प्रावधान प्रशासक जनरल में निहित शक्तियों के दायरे और उन परिस्थितियों को परिभाषित करते हैं जिनमें वह उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है। अनिवार्य रूप से, प्रशासक जनरल उस व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा के लिए कदम उठाता है जिसकी मृत्यु हो गई है और ऐसा कोई भी व्यक्ति सामने नहीं आया है जिसके लिए किसी भी अदालत के पास संपत्ति के प्रशासन का अधिकार क्षेत्र हो। प्रशासक जनरल प्रशासन पत्र प्राप्त करने के लिए उच्च न्यायालय में जाने के लिए कानून द्वारा अधिकृत है। जहां मृतक की संपत्ति या संपत्ति आसन्न खतरे में है, उच्च न्यायालय द्वारा प्रशासक जनरल को संपत्ति की सुरक्षा के लिए तत्काल कदम उठाने का अधिकार दिया जा सकता है। प्रशासक जनरल को प्रशासन पत्र प्रदान करने के लिए उच्च न्यायालय में आवेदन करने की अनुमति देते हुए, कानून किसी अन्य व्यक्ति को उच्च न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने और दावा स्थापित करने की अनुमति देता है। जहां प्रशासक जनरल की प्राथमिकता में प्रोबेट या प्रशासन पत्र का दावा स्थापित हो जाता है, वहां उच्च न्यायालय द्वारा निरस्तीकरण का आदेश पारित किया जा सकता है। ऐसे न्यायिक कार्य उच्च न्यायालय को सौंपे जाते हैं। प्रशासक जनरल, एक सार्वजनिक अधिकारी के रूप में, क़ानून में विज्ञापित परिस्थितियों में एक मृत व्यक्ति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के प्रशासन को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए कर्तव्यों और एआईआई दायित्वों से सम्मानित किया जाता है। कानून ने प्रशासक जनरल को न्यायिक शक्ति आरक्षित नहीं की है। संसद ने अपने विवेक से प्रशासक जनरल को ऐसी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देकर यह सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान किए हैं कि जो व्यक्ति अपने पीछे कानूनी उत्तराधिकारी नहीं छोड़ते हैं उनकी मृत्यु के बाद संपत्ति बर्बाद न हो। उच्च न्यायालय को न्यायिक कार्य सौंपने से सत्ता के दुरुपयोग से सुरक्षा मिलती है और निजी दावों पर निर्णय की सुविधा मिलती है।

24. वर्तमान मामले में, ऊपर बताए गए कारणों से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि कलेक्टर ने स्पष्ट रूप से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया और न्यायिक कार्यवाही शुरू कर दी। यह शक्ति उसमें निहित नहीं थी। इन कार्यवाहियों में दायर जवाबी हलफनामा उत्तराखंड राज्य में लागू उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 167 की उपधारा 2 के प्रावधानों पर निर्भर करता है। धारा 67 की उपधारा 1 और 2 इस प्रकार प्रदान करती हैं:

"167 (1) प्रत्येक स्थानांतरण के संबंध में निम्नलिखित परिणाम होंगे जो धारा 166 के आधार पर शून्य हैं, अर्थात्-

(ए) स्थानांतरण की विषय-वस्तु, स्थानांतरण की तारीख से, सभी बाधाओं से मुक्त राज्य सरकार में निहित मानी जाएगी

(बी) हस्तांतरण की तिथि पर भूमि पर मौजूद पेड़, फसलें और कुएं, उक्त तिथि से सभी बाधाओं से मुक्त राज्य सरकार में निहित माने जाएंगे; और

(सी) अंतरिती ऐसी भूमि पर मौजूद अन्य चल संपत्ति या किसी अचल संपत्ति की सामग्री को हस्तांतरण की तारीख पर ऐसे समय के भीतर हटा सकता है जो निर्धारित किया जा सकता है।"

"167 (2) जहां कोई भूमि या अन्य संपत्ति उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार में निहित हो गई है, कलेक्टर के लिए यह वैध होगा कि वह ऐसी या अन्य संपत्ति पर कब्जा कर ले और यह निर्देश दे कि ऐसी भूमि या अन्य संपत्ति पर कब्जा करने वाले किसी भी व्यक्ति को वहां से बेदखल कर दिया जाए। इस तरह के कब्जे को लेने या ऐसे अनधिकृत कब्जेदारों को बेदखल करने के प्रयोजनों से, कलेक्टर आवश्यक होने पर ऐसे बल का उपयोग कर सकता है या करवा सकता है।

25. धारा 167 की उपधारा 2 द्वारा कलेक्टर को प्रदत्त शक्ति का प्रयोग केवल उपधारा 1 में निर्धारित परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। वर्तमान मामले में, प्रावधान स्पष्ट रूप से लागू नहीं था।

26. उपरोक्त कारणों से, हम अपील की अनुमति देते हैं और 15 मई 2007 के उच्च न्यायालय के आक्षेपित फैसले को रद्द करते हैं। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका की अनुमति दी जाती है और कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 12 मई 2003 को निरस्त कर निरस्त किया जाता है।

27. सिविल अपील का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है। लागत के संबंध में रियो आदेश होगा।

कल्पना.के.त्रिपाठी

अपील की अनुमति।

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से अनुवादक रुचिका गुलेच्छा द्वारा किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।